SHRI D. RAJA: Sir, I move:

(No. 10) That at page 2, *for* lines 9 to 14, the following be *substituted,* namely:—

"(3A) It applies only to the nuclear installation wholly owned or controlled by the Central Government either by itself or through any authority or corporation established by it or a Government company".

The question was put and the motion was negatived.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2010

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration."

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

Sir, it is a long-standing demand on the part of the non-resident Indians. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Hon. Members, please follow the decorum. ...*(Interruptions)*... Please, please...*(Interruptions)*... Please don't talk. ...*(Interruptions)*... What is this? ...*(Interruptions)*... Those who want to move out can do so. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, there are as many as 25 million non-resident Indians. There has been a long-standing demand on the part of the NRIs. We always fail to differentiate between the non-resident Indians and the people of Indian origins, called PIOs and overseas citizens of India (OCIs), and categorize the entire Indian Diaspora as NRIs, which is not correct. It is only the non-resident Indians who are Indian citizens by definition and hold valid Indian passport, nevertheless, for some educational and employment reasons, they have been residing outside India.

We must know that voting right is being given to the NRIs, not the PIOs and OCIs and this is not very unique to India. In many countries like Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Columbia, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Honduras, Italy, Luxemburg and so on, they are given this kind of right. I don't think that Indian citizens who are holding the legitimate and genuine passports should be denied vote. This is a long-standing demand and I put it across the House for consideration.

The question was proposed.

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र): सर, यह जो बिल आया है, It says, "It is to provide the voting right to the Non Resident Indians." Nobody will object to the purpose of it. Originally, there is a provision in the present law that voting right is granted to the citizens who are ordinarily staying at that place. तो यह प्रॉविजन बदलने की बात है। हमारे देश में एनआरआईज़ का कंट्रिब्युशन बहुत है। वे अपने ही सिटीजन हैं। वे शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बाहर गए हैं, उनको देश से लगाव है, वे वोट करना चाहते हैं, वे भागेदारी करना चाहते हैं, वैसे भी वे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैन हिस्सा है, जो ओवरसीज़ एनआरआईज़ रह रहे हैं। उन एनआरआईज़ का जो कंट्रिब्युशन है, inward remittances है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से कोई मतभेद नहीं रखेगा, जो एम. वीरप्पा मोहली जी ने रखा है। But my basic objection is, and it is always for all such amendment, that we are very casual in our approach. My first question regarding this Amendment Bill is: How are they going to vote? Nothing has been specified and we have experience on our hand. सेना के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, उनको अधिकार दिया गया था कि वे जहां भी होंगे, place of ordinary residence पर नहीं रह रहे हैं, फिर भी, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। इसको लगभग सात साल हुए, लेकिन 2009 के लोक सभा चुनाव में एक परसेंट सैनिकों का भी वोट नहीं पड़ा था। अभी तक एक परसेंट सैनिक वोट नहीं कर पाए हैं। ऐसे कानून बनाने का क्या मतलब है? आप कागज पर अधिकार देंगे, लेकिन उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके लिए व्यवस्था क्या होगी, यह इसके साथ बताया नहीं है? See, we have the experience and we have gone to the Election Commissioner. जो सेना की प्रक्रिया बनाई थी, वह इतनी जटिल बनाई कि सेना के लोग यहां से मतपत्र ले जाएंगे, फिर वह कहां, किस पोस्ट पर है, वह कौन से जिले की कौन सी कंन्स्टिचूअन्सी में वोट करता है, वह देखा जाएगा और उसका मतपत्र उसको मिलेगा और फिर वह मतपत्र पर लिखकर भेजेगा, ऐसा होता नहीं है। एक परसेंट भी उनकी वोटिंग नहीं हो रही है। अगर इस देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों का एक परसेंट वोट भी आज भी चुनाव प्रक्रिया में कानून बनाने के बावजूद नहीं गिर रहा है, तो क्या गारंटी मोइली साहब दे रहे हैं कि ये वोट एनआरआई को देने के बाद कैसे आएगा? दुनिया के कई देशों में इंटरनेट वोटिंग है, लेकिन अपने यहां इसका प्रॉविजन नहीं है। आपको प्रत्यक्ष जाकर वोटिंग करनी पड़ती है या पोस्टल बैलेट का अधिकार दो तरह के लोगों को दिया गया है — एक जो चुनाव के काम में लगे होते हैं और दूसरे जो सीमा पर तैनात हैं।

जैसा मैंने कहा कि जो वहां पर तैनात हैं, उनके वोट भी नहीं आते हैं, तो फिर NRI का वोटिंग कैसे होगा, वे क्या करेंगे, पोस्टल भी नहीं हो सकता है। इसकी 22 से 24 दिन की प्रकिया है और 24 दिन की प्रकिया में उम्मीदवार का नाम छाप कर जो बैलेट पेपर तैयार होगा, वह उसके पास कब जाएगा और कब आएगा। आपको इसके साथ ही उस कानून को बदलना चाहिए था, जिसमें इन्टरनल वोटिंग का प्रोविजन करना है। यह कानून पूरी दुनिया में चलता है। हमारे देश में एक ही दिन में सुबह सात बजे से सायं पांच बजे तक वोटिंग होती है। अन्य देशों में वोटिंग के लिए दो-तीन दिन का समय रखा जाता है और वोटिंग मशीन 24 घंटे खुली रखी जाती है। अनेक लोग समय अभाव के कारण एक दिन में अपना वोट नहीं डाल सकते, तो वे दूसरे दिन अपना वोट डाल सकते हैं। आपने चुनाव सुधार का ऐसा कोई विचार नहीं किया है, केवल सहानुभूति जताने का और overseas India का सम्मेलन होता है, भारत दिवस पर, तो भारत दिवस पर एक आश्वासन दिया है कि आपको dual citizenship देंगे और आपको वोटिंग का राइट देंगे, इसलिए बिल लाए हैं। आपने उस पर कोई तार्किक विचार नहीं किया है और न ही उसकी कोई व्यवस्था की है, नहीं तो आप उस व्यवस्था के बारे में हमें जरूर बताते और उसमें भी संशोधन करते। Therefore, I really oppose this casual approach of the UPA Government. It should really be a comprehensive thinking. It should really be a totally well thought-out plan so that the change which you are proposing will be brought into practice. पर

यह नहीं है। आज यह जो बिल आया है, इसमें यह हो रहा है कि NRI वोट कैसे देगा। NRI की एक दूसरी category भी है। उन्होंने दो categories बताई हैं— एक Persons of Indian Origin, PIO लेकिन those who have acquired citizenship और कई पीढ़ियों से वे वहां पर रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। मैं कम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, इन categories में दो करोड़ लोग हैं। इन दो करोड़ लोगों में अगर PIO हैं, तो वैसे भी हैं, जिन भारतीयों ने overseas citizenship प्राप्त की है, उनकी भी संख्या है। एक तीसरी category है, जो परमानेन्ट रेजिडेंट्स हैं, परमानेन्ट वर्क परमिट है, यहां आपकी व्याख्या में वे आ रहे हैं, या नहीं आ रहे हैं, कृपया इसका खुलासा भी किया जाए। इसमें यह मुद्दा है कि वे क्या करेंगे?

हमारे कानून में एक पेचीदा बात है कि जो आदमी जेल में है, वह वोट नहीं डाल सकता, लेकिन उम्मीदवार बन सकता है। जिसको दो साल की सज़ा हो चुकी है या जुडिशल कस्टडी में है, वह वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन वह उम्मीदवार बन सकता है। अब इससे तो NRI को वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन वह कैसे वोट डालेगा, यह नहीं बताया है। क्या वह उम्मीदवार बन सकता है, इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। क्यों खुलासा नहीं किया गया है? अगर उसको वोटिंग राइट दे रहे हो तो फिर केंडिटेट बनने से कैसे रोक सकते हो? Why are you not answering that? अगर देना है, तो पूरा अधिकार दे दो और पूरा विचार करके दे दो, नहीं तो ऐसे लीपापोती मत करिए। यह सब लीपापोती है और कुछ भी नहीं है। अच्छी कल्पना होने के बावजूद अगर उस पर सही अमल नहीं हो रहा है, तो ये केवल कागजी कानून ही रहेंगे। और इन पर अमल नहीं होगा। मेरी आप से यह मांग है कि जो अधिकार सेना को मिला है, उसके बारे में भी मंत्री महोदय बताएं कि उसका कैसे अमल होगा। जो दिया है, उसको तो कर नहीं रहे हो। अनेक सैनिक जब मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें वोट डालनी है। इस बार तो उनमें वन रैंक, वन पैंशन का इश्यु काफी प्रभावी था और आज भी है, इसलिए उन्होंने यह तय किया है कि हम वन रैंक वन पैंशन के पक्ष में वोट देंगे। वे वोट कैसे देंगे? क्योंकि उनके पास मत पत्रिका पहुंचती ही नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। यह इसलिए है, क्योंकि हर तीन महीने में उनकी पोस्टिंग बदलती रहती है। सेना के जवानों का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है। सेना के जवान को अधिकार देने के सात साल बाद भी अगर उस पर अमल नहीं हुआ है, तो इसके बारे में पहले सरकार को एकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। उसको यह जवाबदेही देनी पड़ेगी। वह न देते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री ने एन.आर.आई. को आश्वासन दिया है कि आपको वोटिंग राइट देंगे, सब जगह बैनर लाइन पर छपा था, इसलिए केवल एक नई खानापूर्ति करने के लिए बिल ला रहे हैं, अगर यही प्रोविजन है तो इससे कुछ नहीं होगा, यह केवल एक कागजी कानून बनकर रहेगा, यह अधिकार केवल कागज पर रहेगा, इस पर वास्तविकता में कुछ अमल नहीं होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार सेना के अधिकार के प्रयोग का खुलासा करे। इसको कैसे करेंगे, सरकार इसका ऐक्शन प्लान भी लाए। हम इसके लिए सुझाव देने के लिए तैयार हैं। आप मीटिंग बुलाइए, इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग बुलाइए, एक प्रोसिजर तय करेंगे, जिससे यह बात सुलभ होगी। इसके साथ ही साथ एन.आर.आई. की वोटिंग कैसे होगी, इसका भी खुलासा होना चाहिए, वह उम्मीदवार का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है, यह भी आपको बताना पड़ेगा कि, He will be a voter but he cannot be a candidate. Or, at least, that is ambiguous. इसलिए मैं मांग करता हूं कि अगर इस बारे में विचार करके कुछ ऐक्शन प्लान देंगे, तो इसका समर्थन करने का मतलब है, नहीं तो यह केवल एक कागजी खेल है। थैंक यू, सर।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I rise here to support the Representation of People (Amendment) Bill, 2010. In fact, Sir, I was a little worried at the fag end of the Session whether this Bill will come at all or not. From my point of view, Sir, and from the point of view of the Chair also, this Bill is very important. Our two States, Goa and Kerala, are maximum affected. Karnataka is also affected because of this. Now, Sir, why was this Bill needed? Why

was the need of this Bill felt? In my humble opinion, till today, the definition of ordinary resident, as interpreted by the Election Commission, was not correct. As the law stands itself, people who are in Gulf countries, people who work on board a ship, are still entitled to vote, and they were and they are the ordinary residents of the place. It is because the officials of the Election Commission, in their respective States, interpreted the word ordinary resident wrongly, names of lakhs and lakhs of voters were removed from the electoral roll. Therefore, it is shocking, I would say. We are passing this Bill today and their rights will, no doubt, be restored, but this aberration should not have been there. I would like the Law Minister to take this into consideration. You have to take a lot of trouble to see that the Bill is introduced when it was not necessary. It is because of wrong interpretation by the Election Commission officials that we have to take this exercise, and it took long three years for us to restore this. The Election Commission should be the main authority to understand the democratic values. Who should understand the voting right of the people? It is the Election Commission. The Election Commission itself is doing such a thing which we cannot understand. This has not happened with respect to voting right only. There are many other such things, Sir. Now, Sir, those who work in Gulf countries, where is their house? They have gone from their house. They are working on board a ship. Does the Election Commission say that the ship is their house? Why were their names removed? Somebody should answer this. They don't have a house. They are working temporarily there and the names of such people were removed. Will anybody answer this? Those who work temporarily in small barracks in Gulf countries, their names were removed. Who removed their names? What was the interpretation of an ordinary resident? Will somebody reply to this question? It may be that those who have done this are constitutional authorities. We are a body created by the Constitution. We have the right to ask that body as to why those names were removed. It is not a simple matter. Every time a law is interpreted by the Election Commission, we have to bring amendments to restore our rights. Where will it end? This is not a simple matter. You should have a thorough study of it and find remedies.

I would just read Article 324 (1) of the Constitution. It says that the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of election to the offices of President, etc., lie with the Election Commission.

Does this give the Election Commission power to make laws? In the name of Article 324, the Election Commission issues letters in every election. And during election period, every day a letter is issued and it says that its letters are the laws. The letters issued under Article 324, the directions given under Article 324, and the circulars issued under Article 324 on all the subjects, which come under its jurisdictions, are the laws of the State. The Election Commission should understand our powers. This precedent was, unfortunately, laid down by the earlier Chief Election Commissioner, Mr. Seshan. Mr. Seshan used to say, 'My powers under Article 324

supersede the power of Parliament of India.' He used to make such statements. Somehow the tradition laid down by Mr. Seshan, unfortunately, is being followed — I would not say the present regime follows it totally — but to a lesser extent.

Look at the "laws" created under Article 324 by the Election Commission. They are voluminous. You look at the number of pages. And look at the Representation of People Act, 1950 and the Representation of People Act, 1951. If you look at the letters written by the Election Commission, they are as voluminous as these laws. Laws created by the Election Commission are voluminous.

Sir, one day I went to Mr. Moilyji and he was kind enough to take note of my submission. I told him whatever letters had been written by the Election Commission, whatever circulars had been issued under Article 324 — which I am saying 'illegal' — if they contain some good suggestions, incorporate them in the law. It is our power. But don't let our power to be exercised by the Election Commission through its letters.

Lastly, Sir, we are in a hurry to pass this legislation. Let the Election Commission decide as to which law passed by Parliament will regulate the conduct of expenditure and general observers during election. When elections take place, two kinds of observers go there. One is expenditure observer and the other is general observer. They create their own laws in the constituencies. They go to campaign office and see what you are eating and what your workers are eating. Suppose a worker is eating a samosa, they will say that its cost is ten rupees. Some worker is putting on a cap, they will say that its cost is twenty five rupees. They will decide the rate. This will affect your expenditure ceiling. Those people decide the rates of a cap or a T-shirt or a samosa or a soft drink or a *mandap*. Even if a *mandap* does not have chairs, the observer will charge five hundred rupees as rent for 500 chairs.

Sir, these things appear to be minor but they affect all the candidates who contest elections. Sir, the Election Commission has to be told that under article 324, their powers are very, very limited. And, if they don't listen, you have to specifically amend article 324 to restrict the powers of the Election Commission. Thank you, Sir.

श्री अवतार सिंह करीमपुरी (उत्तर प्रदेश): थैंक्यू, सर। हमारे माननीय मंत्री जी "The Representation of the People (Amendment) Bill, 2010" लाने के लिए बधाई के पात्र हैं। इसके माध्यम से जो भारतीय विदेशों में जाकर बसे हैं, उनको हम भारत में वोट का राइट देने जा रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय अपने रोज़गार के लिए, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों मे जाकर बसे हैं। लेकिन हम जिन एनआरआईज़ का नाम वोटर लिस्ट में ऐनरोल करेंगे, वह कैसे होगा? टाइम टू टाइम इलेक्शन कमिशन जब वोटर लिस्ट को रिव्यू करता है, उस वक्त वोटर का प्रैज़ेंट होना जरूरी होता है, अदरवाइज़ उसमें से उसका नाम निकाल दिया जाता है। मंत्री जी इसके लिए क्या प्रावधान कर रहे हैं? हमारे जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐनरोल करने का क्या प्रोवीज़न है और उसको कैसे कंटीन्यू रखा जाएगा? मेरा सुझाव है कि इसमें इस तरह की पारदर्शिता हो और ऐसी व्यवस्था हो, जिससे बार-बार उन्हें नाम ऐड करवाने के लिए न आना पड़े या फिर उसको कंटीन्यू करने

के लिए न आना पड़े। इसके लिए क्या प्रवीज़न हो सकता है, यह जरूर सोचा जाना चाहिए। हमारे पंजाब के भी बहुत से भाई बड़े पैमाने पर इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, यूरोप, यूएई वगैरह कंट्रीज़ में बसे हुए हैं।

महोदय, हम देखते हैं कि अगर एक मां का बच्चा आधा घंटा भी देरी से पहुंचता है तो उस मां को नींद नहीं आती है, वह देखती है कि मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया है। लेकिन, आज जब विदेशों में रह रहे भारतीयों को हम वोट का राइट देने जा रहे हैं, तो हमारी सरकार को भी इस बारे में सोचना है कि हमारे करोड़ों भारतीयों ने भारत देश को छोड़ कर आखिर क्यों दूसरे देशों में जाकर बसने का फैसला किया। आखिर क्यों उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ा, जिस मां ने जन्म दिया, उसको छोड़ा, पिता को, भाई को, बहन को सबको छोड़ा। जिन अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए भारतीय फांसी पर लटके, आज वही भारतीय पेट की खातिर उन्हीं अंग्रेजों के शासन में जाकर अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब देश की आजादी के आंदोलन के संचालक यह कहते थे कि इस देश में भूख का कारण अंग्रेज हैं, गरीबी का कारण अंग्रेज हैं, शोषण का कारण अंग्रेज हैं, अन्याय और अत्याचार का कारण अंग्रेज हैं। अंग्रेजों को निकालो तो सब ओर साधन सम्पन्नता हो जाएगी। सब का सम्मान होगा और किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। देश की जनता ने कुर्बानियाँ दीं। कोई कालेपानी गया, कोई जेलों में रहा, किसी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जालियाँवाला बाग का साका हुआ, जहाँ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हजारों लोगों पर गोलियाँ चलाई गईं।

आज हमें इस बात पर भी सोच करनी है कि क्यों उन अंग्रेजों के राज में जाने के लिए हमारे भारतीय अपनी माँ, पिता और जन्मभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए हमें फाँसी के रस्से को चूमना पड़ा? मैं यह समझता हूँ कि यह आज तक की हमारे केन्द्र की सरकारों का फेल्योर रहा है कि हम इस देश के पोटेंशियल को नहीं संभाल पाए हैं, हम इस देश के वासियों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। यह तो ऐसा ही काम है जैसे 63 साल की आजादी में जिन गरीबों को झुग्गी दी है, उनकी झुग्गी में अब चाय पी जा रही है। इसी तरह से जिनको हम देश में रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिनको हमारी सरकारों ने मजबूर कर दिया कि आप अपना परिवार छोड़ो, अपनी माँ, बहन और भाई को छोड़ो और विदेशों में जाओ, उनको अब हम वोट देने का एक राइट देने जा रहे हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि जो मूल समस्या है, उस के लिए हम सोचें, हम इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करें कि किसी भी भारतीय को कम-से-कम पेट की भूख की खातिर और अपनी पारिवारिक जरूरतों की खातिर अपना देश न छोड़ना पड़े।

सर, हमारी सरकार के पास शायद यह आँकड़ा हो या न हो, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं। मैं अभी कह रहा था कि माँ इंतजार करती है कि मेरे बच्चे के आने में देर क्यों हो रही है, वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? हजारों बच्चे ऐसे हैं, जिनको उनकी माँ अपने सीने पर पत्थर रख कर घर से किसी एजेंट के हाथ मे पकड़ा देती है। वह उसको जंगल में ले जाता है या समुद्र में किश्ती में कहीं ले जाता है। उसे जहाँ कहीं पहुँचने का झाँसा दिया जाता है, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही उसको समुद्र में डुबो दिया जाता है। आप उसको कैसे वोट का राइट दे सकेंगे, जिस माँ का पुत्र वापस नहीं आया? हमारे पंजाब में हजारों ऐसी माताएँ हैं, हजारों बहने ऐसी हैं, जिनके पुत्र और भाई वापस नहीं आए हैं। उनके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। हमें एक कारगर नीति बनानी पड़ेगी। इस देश के अन्दर इम्प्लॉयमेंट के ज्यादा-से-ज्यादा मौके जेनरेट करने होंगे, ताकि हमारे किसी भी भारतीय भाई को, किसी भी भारत के वासी को, किसी भी भारतीय को, अपने पेट की खातिर, भूख मिटाने के लिए विदेशों में जाकर अपने आपको सरेंडर न करना पड़े।

सरकार यह जो बिल वोट का राइट देने के लिए लाई है, ...(**समय की घंटी**)... इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि साथ-ही-साथ सरकार एक ऐसी संजीदा नीति बनाए जिससे हमारे देश का जो नौजवान है, जो हमारे देश का पोटेंशियल है, उसको देश के बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।

उपसभाध्यक्ष **(प्रो. पी.जे. कुरियन)**: धन्यवाद, करीमपुरी जी। ...**(व्यवधान)**... Now, Shri P. Rajeeve. *.....(Interruptions).....*

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I rise to support this Bill. I thank you, Sir, this is the first time I got an opportunity to support a Bill moved by this Government. This is a long-standing demand of the Non Resident Indians; the Government of Kerala has also submitted several memoranda to the Central Government for giving voting rights to the Non Resident Indians. My party, Community Party of India (Marxist) also raised the slogan for giving the voting rights to NRIs for several decades.

Actually, this is a belated introduction. The Ministry had introduced this Representation of the People (Amendment) Bill in 2006 and the Standing Committee had submitted its Report on 4th August, 2006. The Ministry has been sleeping over this Bill for four years. Anyway, it is a belated introduction and I welcome this Bill.

Sir, I come from the State of Kerala. Thirty-five lakhs of Malayalees are working outside India and most of them are working in the Gulf countries. Their contribution to the State domestic product is 25 per cent. They take keen interest in the affairs of the country and they are also participating in the nation building activities through various methods. They are also helping to mobilise resources for the development of the nation.

Sir, Kerala is one of the model States in our country in protecting the interests of the Pravasis by enacting various legislations, taking welfare measures and setting up welfare mechanisms. Now, the State Government has constituted a Pravasi Board for the welfare activities of Pravasis. It includes different schemes like insurance scheme to protect the returnees from Gulf countries. But actually the Central Government has done nothing for the welfare of the NRIs. It is a good move to give voting rights to the NRIs. But it has done nothing for the welfare of the NRIs. The constitution of the new Ministry, the Ministry of Overseas Indian Affairs, is a good move. The Ministry has taken some initiatives. But it is working with empty hands. The allocation to the Ministry is Rs.80 crores. The total number of Indians working outside is more than 25 millions and the allocation is only Rs.80 crores. I request the Government to provide more allocation to the Ministry. I urge upon the Government to take up more welfare activities for the benefit of the NRIs who are contributing to the development of the country.

Sir, the Government collects huge amounts, crores of rupees, as Emigration Fund. It utilises the fund for the benefit of other schemes and not for the welfare of the Pravasis. I would like to take this opportunity to urge upon the Government to utilise this Emigration Fund for the welfare of the NRIs exclusively.

Sir, in the Census process, there is no mechanism to include the names of the NRIs. While giving the voting rights to the Pravasis, there should be some mechanism under the Ministry of Home Affairs to include the names of the NRIs in the Census process.

Sir, as regards the situation in the Embassies, I would like to know whether the Government is ready to evaluate the strength of the workforce in the Embassies. Several lakhs of Indians are

working in the Gulf countries. The existing staff strength in European countries and the USA is much more than in the Gulf countries. So many people approach the Embassies in the Gulf countries, but there are no facilities and the staff strength is quite inadequate to address the genuine issues of the NRIs living in the Gulf countries. So, I request the Government to evaluate the staff pattern and also allocate adequate funds to the Embassies in different countries.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, he is talking of the shortage of staff strength in the Embassies. That is what he is saying.

SHRI P. RAJEEVE: The hon. Minister is more aware of this issue than me. If he is ready to give an assurance in this House, I will be happy.

Sir, article 326 of the Constitution of India says that every person who is a citizen of India, who is not less than eighteen years of age and who is not otherwise disqualified under the Constitution or any law made by the appropriate Legislature is entitled to be registered as a voter. There is a provision in the Constitution. But there are some provisions in the Representation of the People Act and other legislations which prohibit voting rights to the NRIs who are not residing at their local address for the prescribed months or years.

This is a good move to give the right to vote to the NRIs. But the Standing Committee in its report has mentioned that Section 20 of the Representation of the People Act, 1950, already contained a number of exemptions to the term 'ordinarily resident'. There are seven exemptions to this term 'ordinarily resident'. The Standing Committee has recommended, "If one amendment can satisfy all other exemptions, why don't you bring a simple amendment by which you can carry out all other seven exemptions? Increasing the number of exemptions is making the law complicated". This is the recommendation of the Standing Committee on the previous Bill, 2006. Is the Ministry aware of that? Why hasn't the Ministry taken interest to formulate a single amendment to incorporate all these exemptions to the term 'ordinarily resident'?

Although, 'citizen' has been defined in the Constitution and other categories of citizenship have been defined in the Citizenship Act, 1955, but the term 'NRI' is not statutorily and legally defined anywhere and is understood in common parlance. Although, 'NRI' has been referred to in the IT Act 1961 only, but I request the Ministry to give a legal definition to the term 'NRI'.

Sir, the Minister has stated in his introductory remarks that several countries have already given voting right to their citizens working abroad. These countries have recognized the political right of their citizens residing in other countries. However, they follow different practices in this regard and have imposed different conditions or laid different criteria while allowing them the right to vote and contest elections in the country of their origin.

While concluding, I would like to mention one ambiguity so far as this Bill is concerned. There should be some distinction between the voting right and right to contest. The Standing

Committee has also made a recommendation that every citizen of India who has not acquired the citizenship of any other country should be deemed to be resident of India. The NRI who has acquired a citizenship of any other country, according to my understanding, there is no mechanism to verify whether a person is having dual citizenship. This should be defined clearly in the Bill. Whether the green card holders have the right to contest the election, there is some ambiguity in this regard. I request the Government to clarify the two issues regarding voting rights and right to contest. Therefore, I urge the Government to formulate a rule and provide this in the Bill. Thank you.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand here to support the Representation of the People (Amendment) Bill, 2010. I am very happy that this amendment has been brought to give an opportunity to the Indian citizens to participate in the election process, who are living outside the country. There are millions of Indians living throughout the world in different continents and countries. Many of them are highly educated; they are scientists, prominent journalists, writers, industrialists, engineers, doctors and along with them there are thousands of skilled and unskilled workers working outside India. They have every democratic right to participate in the election process, in the democratic process in this country. They have been demanding this since so many years. Now the Government has brought this Bill. It seems that there are certain lacunas. I think no proper arrangements have been made to enroll them as voters.

There is no proper arrangement for them to cast their votes. So, unless they are given an opportunity, like the Indian citizens here, how will they enroll their names in the voters' list; and how will they cast their votes in a foreign land? So, in this connection, I want to give some suggestions. Many of my colleagues have also suggested certain steps to be taken. Sir, we have our diplomatic missions in different countries? Why should we not take the services of our diplomatic missions to arrange for enrolment of those persons, and also enable them to cast their votes. In other countries, be it Europe or the U.S. or any other country, they have a similar provision for their foreign residents to cast their votes and participate in the democratic process of election. But, here, in India, we cannot do it in the same way. I wonder whether we can give the responsibility to our diplomatic mission to carry out this job. I do not know how far it will be viable. The hon. Minister can look into this matter.

Another thing is regarding dual citizenship. I feel that those who are having citizenship of another country should not be given an opportunity to participate in voting, and they should also not be given an opportunity to contest the election. It has to be seen whether those people, who are not having dual citizenship or citizenship of other countries, can participate in the election process here. That should be looked into. Another thing is regarding voting process. They should be given all the opportunities to participate in the elections.

7.00 P.M.

Now, some of my friends have raised the question about Armed Forces working outside our country, in foreign lands. They are on a diplomatic mission, and they have an opportunity to vote. The postal voting system is there. But this does not apply to workers working, say, in Gulf countries. They are sending money to our country. They are helping our country. We want that those intellectuals or professors or industrialists, should also be given an opportunity to strengthen the emotional relationship with their country, and if we give them the opportunity to vote, that is, take part in the voting process, or, enroll their names in the voters' list, that emotional relationship will last long in them, and they will be encouraged to participate in the nation-building. With these words, I support the Bill.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, on behalf of my party, the DMK, I, wholeheartedly, support the Representation of the People (Amendment) Bill, 2010. Our leader has been insisting upon the demand to include citizens who are away from their residence for employment, education or any other purpose and to enable them to vote. Sir, the Representation of People Act, 1950, makes a detailed provision for elections and lays down conditions required for a person to register himself as a voter in a constituency. Whenever we happen to travel abroad, the Indians, who are there, have been persistently telling us to get them the voting rights. Just because they are away on an employment, they should not be deprived of the voting rights. We have also been representing on their behalf, and the Government of India has taken a right decision. Section 19 of the Representation of the People Amendment Act, 1950, provides that every person, who is not less than 18 years of age on the qualifying date and is ordinarily a resident in the constituency, shall be entitled to be registered in the electoral rolls for that constituency.

The meaning of 'ordinarily resident' is laid down in section 20 of the said Act. In 2006, the Government brought an amendment to this Act to enable Indian citizens, absenting from the places of ordinarily resident, to register themselves as voters. When this Bill was referred to the Standing Committee, it gave certain recommendations and insisted on a comprehensive Bill. So, that Bill was subsequently withdrawn and the recommendations of the Standing Committee have also been included in the Bill, which is brought in now.

One or two observations I would like to make on the recommendations which the Standing Committee has made and what has been implemented in the Bill. Sir, the Standing Committee has said that the Bill had not defined the term 'temporarily resident' although it seeks to create a class of citizens. 'A citizen of India', it suggested to reword: "The citizen of India who has not acquired citizenship of any other country shall be deemed to be resident in India in any constituency of his choice notwithstanding his residence outside India, whatever its duration." So, the present Bill which is being discussed now allows for all citizens to be enrolled in the electoral rolls in the constituency in which his place of residence in India is as mentioned in his

constituency. Earlier, mere ownership of a property by a person in a place did not entitle him the right of voting, just because he has gone abroad for employment or something. Through this Bill, the electoral officer has to undertake the required verification for enrolment. The procedure for registration and the time period within which the registration shall take place is to be specified by the Government in consultation with the Election Commission. Sir, the Standing Committee's recommendations have been conceded by the Government and the Bill has included those.

Sir, another important thing which the Standing Committee has said is that the term 'non-resident Indian' is not defined. It was in the earlier Bill. Now, the 2010 Bill, which has replaced the 2006 Bill, permits registration in the electoral rolls of persons (a) who are citizens of India and (b) not enrolled in electoral rolls (c) who have not taken up the citizenship of any other country, and (d) who are absent from the ordinary place of residence.

Another important thing is, the 1960 rules provide for notice and a reasonable opportunity to be heard before a person's name is deleted. In actual practice, the names are deleted without following the procedure. The Standing Committee expressed its concern over large-scale deletion of names and recommended that the procedure for deletion of names should be strictly followed. This has been an issue for long and this Bill addresses that issue also. The Bill specifies deletion from the electoral rolls can happen only after due verification and the procedure for it. So, Sir, this Bill not only addresses the long-pending issues of NRIs who are abroad; it has also accepted most of the recommendations of the Standing Committee. This is a welcome Bill which will be a very good news for our people abroad.

I welcome this Bill, Sir. I thank you for the time given.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri N. Balaganga, speak in Tamil.

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): * Hon'ble Mr. Vice Chairman Sir, I thank you very much for granting me this opportunity to speak on this Representation of the People (Amendment) Bill, 2010. "Cross the tumultuous sea in search of property", says a Tamil proverb. Accordingly, since ancient times, Indians particularly Tamils, have travelled abroad for trade related activities and in search of employment. Various factors such as scientific development, development in higher education, population explosion etc. have created such a situation that it is impossible for every Indian to get employment in India itself.

There are more than four hundred and seventy one engineering colleges in the State of Tamil Nadu. We have more than one and a half lakh engineering graduates every year. It is not apt to expect that all of them would get employment in India itself. Schemes like Sarva Shiksha Abhiyan may provide education to all. But neither the Union Government nor the State

*English translation of the original speech in Tamil.

Governments can give employment to all the graduates in India. Therefore, according to their qualification, they go abroad in search of suitable employment. As they are residing abroad for a long time, their names are removed from the electoral rolls. As per the existing rules, their names have to be removed from the electoral rolls. During every election, an intensive exercise is undertaken to prepare electoral rolls. According to the rules of the preparation of electoral rolls, if a person is absent from his house for a particular period, his name is to be removed from the electoral rolls. In this way, the names of non-resident Indians have been removed. As their names are removed from the electoral rolls, an inferiority complex has developed in their hearts that they are losing their citizenship in India. Therefore, they have a longstanding demand to include their names in the electoral rolls and to provide them the right to cast their votes in the elections to the Parliament and to the State legislatures. It is in order to fulfil this long-standing demand that this bill has been brought. We welcome this bill. At the same time, I would like to mention a point made by my dear colleague Mr. Javadekar who said that this bill is too general as it mentions only about the inclusion of NRIs in electoral rolls. But, this bill does not mention the methods to be adopted for inclusion of their names.

Sir, it should be clearly mentioned how their names will be included in the list. During the preparation of electoral rolls, school teachers and Government servants from the revenue department were deputed for the task. The Election Commission do not have sufficient staff of their own for this task. When teachers and Government servants visit for enquiry, they become familiar with all the voters. The voters can be identified by them. If the name of a voter is not found in the electoral rolls, he can get his name included by submitting form 'eight' directly. But how could they identify an NRI who has not resided in his own place of residence? What is the provision for the NRIs to get their names included in the electoral rolls? This point needs to be clearly mentioned in the bill. Sir, I want one more minute. I would like to seek clarification about another important point. When a person gets the right to cast his vote, he is eligible to contest in the elections. Similarly, when the NRIs are given the rights to cast their vote, will they be eligible to contest in the elections? Information with respect this point needs to be provided.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your time is over. Your time is over.

SHRI N. BALAGANGA: Sir, I would like to mention that there should be an exclusive electoral roll for NRIs as there are separate electoral rolls such as primary electoral rolls and supplementary electoral rolls. If such an electoral roll is prepared exclusively for NRIs, details about their residence abroad, name of the country they are residing in also needs to be mentioned.

In addition to the above-mentioned points, I would like to request that the system of Electronic Voting Machines (EVM) may be withdrawn. In the ballot paper form, a person gets a

large amount of satisfaction when he marks the impression on a particular symbol whether it is on double leaf, or on hand or on lotus or on anything else. That kind of satisfaction is not derived when a person presses the button in Electronic voting machine for casting his vote. Therefore, I would like to suggest that the system of Electronic Voting Machines may be withdrawn. By virtue of this bill, lakhs of NRIs who are residing outside India will be given their democratic right to cast their vote in India. Once again, I would like to say that I welcome this bill and I thank you again for granting me this opportunity. With these words, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Time for your party is two minutes, you can take three minutes...*(Interruptions)*... It is 50 per cent increase. ...*(Interruptions)*...

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Thank you, Sir. Sir, I congratulate the Overseas Affairs Minister for bringing this Bill which is a long pending demand of NRIs. NRIs play very important role in the economic development of our country. But we are not able to do justice to the NRIs. They are completely excluded from the democratic process of our country. This Bill is a beginning of taking into account their aspirations. But, as being pointed out here, this Bill has got many limitations. Even though we are giving voting right to them, vast majority of them will not be able to exercise their right. It is not clear whether for the enrolment in the electoral roll their physical presence is necessary. Now their names are not in the ration cards or in the electoral roll or even in census. So, my suggestion is that we have to take an affidavit from their families and include their names in the electoral roll. If we do not insist on the physical presence to include their names in the electoral roll, then only we can give them a chance to vote. For voting they have to come to India. There is no provision to cast their vote outside India. The Government must explore the possibility of giving this facility. In many countries, they allow their citizens to cast their vote in the countries where they are residing. It will not be an easy thing especially in Gulf countries but the Government must explore the possibility and contact the Governments in Gulf countries to find out whether it is possible. Giving voting right is one of the demands of the NRIs. There are many other problems being faced by the NRIs. Especially after the economic recession lakhs of people are coming back to India. We are facing a very difficult economic situation. There is no provision for their rehabilitation. During the last NRI Conference, the Prime Minister announced that there would be some programme to rehabilitate the people who are coming back from foreign countries. ...*(Time-bell rings)*.. But unfortunately, not even one rupee has been earmarked in the last Budget. The Kerala Government is implementing a comprehensive programme for the rehabilitation for the people coming back from Gulf countries. ...*(Time-bell rings)*... They are being given pensions and taking all steps for their welfare. So, the Union Government must evolve some programme to help the NRIs for their welfare. For such a Ministry the allotment is just below Rs.100 crores. My suggestion is that it must be increased to at least Rs.1000 crore for creating an NRI Welfare Fund. The Government must take action for this by providing, at least, Rs.1000 crore, to the Ministry. Thank you.

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Thank you. Sir, I wish that I could support this Bill wholeheartedly. However, since I have some reservations, I would seek some clarifications from the hon. Minister. Sir, here he says that 'people who have not sought citizenship of any other nation'. I take it like this that those who are having dual citizenship - many countries are having dual citizenship — those people will not get the voting right. I think the Government must make it very clear, amply clear that those who have sought or taken citizenship of any other country, whether they have the dual citizenship of this nation or not, they should not be allowed to participate in the voting process. Sir, having said that, I wish to bring it to the notice of the Government, which the first speaker hon. Javadekar actually started, is that there are many people, Indians, living in India, who have been deprived of their voting rights or from registration of their names in the voters' list only because they do not stay permanently at their residence which they have indicated.

For example, Sir, construction workers are all over India. I come from Mumbai. Construction workers from Andhra Pradesh, from Bihar, from Punjab come to Mumbai. They are migrants and they do not have permanent address because they are not found at their residential address and they do not get ration cards from anywhere. So, they are deprived of their voting rights. What does Government do about them? There are many farm workers. I am not talking about the farmers. Those who do not have land holding have to travel from place to place for earning their livelihood. They are always deprived of their voting rights because their names do not come in any voter's list. What do we do about it? Thirdly, we have a large number of nomadic tribes. Nomadic tribes keep travelling from place to place with their tribes. What do we do about them? So, when we cannot do anything about Indians living in India, why are you so much bothered about Indians living outside India? First set them right. First bring them in order and then, start thinking about those who are outside. Another query which I would like to ask is, today we are giving them the right to vote. Tomorrow a demand will come, as hon. Member Shri Achuthan had suggested, that since they will not be able to come to India for voting, then voting can be done there. Sir, this is a dangerous suggestion. If we tell them that okay, you can work anywhere in the world then, why should Indians vote? If we accept that demand, Sir, more dangerous things would come. After a few years those non-resident Indians would come with a demand that they should be allowed to participate and contest elections. What do we do about them? Once we logically agree, once we in principle agree that they can vote, then, all those who have attained the age of 18 can vote and at the age of 25 they have a natural right to contest elections. What do we do about these voters? Sir, these are the issues. Sir, don't go only by emotions. Even my heart beats for them. But that does not mean that I get emotionally choked, emotionally governed and give them the voting rights. I think, the Government should think twice, thrice, take the nation into confidence and then go ahead with the Bill.

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 का समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें जो कुछ कमियां रह गई हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं अपनी असहमतियां भी व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, यह संशोधन विधेयक इससे पहले 2006 में यहां प्रस्तुत हुआ था। आपने इसको 27 फरवरी को सदन में प्रस्तुत किया था। इसमें कुछ शाब्दिक परिवर्तन करने के लिए आपने चार वर्ष लगा दिए। अब आप फिर से इस लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 को सदन में ला रहे हैं। इस सदन का सदस्य बनने के पश्चात् मैं कभी-कभी सोचता हूं, विचार करता हूं कि हमारे देश को सम्भालने की पद्धति क्या है, हम व्यवस्था के प्रति कितने जवाबदेह हैं, कितने उत्तरदायी हैं। पचास-साठ वर्ष बीत जाने के बाद भी हम अपने लोक महत्व के अधिनियम को परिपूर्ण नहीं बना पाए, हम इसको परिपक्व नहीं बना पाए। आज भी उसमें इस प्रकार की खामियां हैं, जिनके कारण हम निर्वाचक मतदाता सूची को ठीक से नहीं बना पाए, यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। लोकतंत्र में निर्वाचक या मतदाता सूची की इतनी बड़ी खामी का होना, सचमुच एक चिंता का विषय हो सकता है।

महोदय, चार वर्षों का प्रयत्न करने के बाद, आपने जो संशोधन किया है, वह संशोधन का शब्द का है और वह है "समुचित सत्यापन करने के पश्चात्"। आपने पहले, 27 फरवरी, 2006 को तीन पंक्तियों का संशोधन किया था, अब चार वर्षों के बाद बाद, सारी खोज बीन करके, प्रयत्नपूर्वक अपनी सारी बुद्धि लगाने के बाद, सरकारी मशीनरी का उपयोग करने के बाद, आप केवल इतना ही खोज पाए कि "समुचित सत्यापन करने के पश्चात्", यह शब्द अंत:स्थापित किया जाए। आप एक शब्द के लिए चार वर्ष लगाते हैं। इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं। इस देश में आज भी मतदाता सूची के बारे में प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। सचमुच भारतीय गणतंत्र के प्रारंभ के साथ इन साठ वर्षों में जो एक कानून बनना चाहिए था, वह कानून नहीं बना। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था। सर, इस विधेयक के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसके दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि जो विदेश में गए हों, यहां से शिक्षा के लिए गए हों, व्यापार के लिए गए हों या अन्य किसी भी कारण से गए हों, यदि यहां उनका निवास है, उनकी संपत्ति है, और वे वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनको मतदान का अधिकार दिया जाए, उनको निर्वाचक माना जाए, यह संशोधन है, लेकिन इसका दूसरा भाग भी है, और दूसरा भाग यह है कि जिन्होंने विदेशी नागरिकता स्वीकार नहीं की है, जो वहां निवास करते हैं, वहां जाने के बाद उनकी संतान हो गई है, संतान होने के पश्चात् वह संतान वहां की संतान मानी जाने लगी, लेकिन जब वे यहां आते हैं, तो चूंकि वे यहां पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतदाता सूची तो ठीक है, उनको शिक्षा और अन्य अनेक प्रकार के जो काम हैं, जो उद्यम करना चाहते हैं, वहां पैदा हुई संतान यहां आकर बहुत कठिनाइयों में पड़ जाती है। मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि उनके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। मेरे एक बंधु ने कहा है कि आपने इसमें अनिवासी या प्रवासी भारतीय की परिभाषा कहीं नई दर्शाई है। वास्तव में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि उसे, उसके पिता या पुरखे को मतदान का अधिकार रहा हो, तो उसको यहां पुन: मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यदि उसके पिता, पुरखे या किसी अन्य को मतदान का अधिकार नहीं रहा हो, कोई निर्वाचक नहीं रहा हो, तो उसको यहां पर, किसी भी प्रकार से, चाहे संपत्ति उसके नाम खरीद ली गई हो, तो भी उसको मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, इसके अलावा भी अनेक ऐसे लोग हैं, जो देश में आ गए हैं। उन्होंने यहां सम्पत्ति खरीद ली है, राशन कार्ड बनवा लिए हैं, वे कई राजनैतिक लोगों के सहभागी बनकर यहां के निवासी बन गए हैं। यदि निवासी बनने के बाद वे जाते हैं, तो आपने इस संशोधन विधेयक में पासपोर्ट को आधार बनाया है कि जिसका पासपोर्ट बना हो, सर, हमरे यहां पर पासपोर्ट बड़ी सरलता से बन जाता है। पासपोर्ट बनाने का आधार क्या है? पासपोर्ट राशन कार्ड के आधार पर बनता है। वह यहां रहता है, तो बिजली का, टेलीफोन का बिल प्रस्तुत करे। यदि वह बिजली और टेलीफोन का

बिल बनवाकर राशन कार्ड प्रस्तुत कर दे तो उसका पासपोर्ट बन जाता है। यहां ऐसे अनेक लोग हैं, जो विदेश से आए हैं। वे विदेश से आकर अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं। वे अपना बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल प्रस्तुत कर देते हैं और उस आधार पर पासपोर्ट बनवाकर चले जाते हैं। यदि वे फिर से यहां आते हैं तो मतदाता हो जाएंगे, उनका नाम निर्वाचक सूची में आ जाएगा। बांग्लादेश के हजारों लोग यहां पर हैं, जो यहां की मतदाता सूची में आ गए हैं। आपने उनके बारे में इस बिल में क्या प्रोविजन किया है? क्या व्यवस्था की है? वे यहां की राजसत्ता को परिवर्तित करने के अधिकारी हो गए हैं। वे इतने ताकतवर हो गए हैं कि जिसे चाहें उसे अपना जन प्रतिनिधि चुन सकते हैं। वे किसी भी विधान सभा में, किसी भी विधायिका में अपने प्रभावशाली लोगों को भेज सकते हैं, सत्ता को उलट-पुलट कर सकते हैं, सत्ता में भागीदार बन सकते हैं और सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पर व्यापक विचार होना चाहिए था। व्यापक विचार करते समय यह भी विचार होना चाहिए कि जो विदेश में जाकर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं, हमारे देश के खिलाफ वहाँ षडयंत्र करते हैं, वे उस देश विरोधी मानसिकता को लेकर यहाँ आएँगे और यहाँ भी षडयंत्र करेंगे, लेकिन वे केवल इस आधार पर यहाँ आकर हमारे मतदाता बन जाएँगे, निर्वाचन बन जाएँगे, क्योंकि वे यहाँ से गए थे, उनकी सामान्य सम्पत्ति थी। वहाँ उनका चरित्र क्या रहा है, वहाँ पर उनका देश के प्रति व्यवहार क्या रहा है, उनकी गतिविधियाँ क्या रही हैं, इनके बारे में आपने कहीं कोई विचार नहीं किया है। मेरा आग्रह है कि इसके बारे में भी व्यापक विचार होना चाहिए और देशहित की भावना से उसमें इस प्रकार के प्रावधान किए जाने चाहिए कि कहीं वह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में सम्मिलित तो नहीं रहा।

महोदय, मैं इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अनेक लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं। दबंग लोग, शक्तिशाली लोग उनको अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने देते। एक तरफ तो हम उन विदेशी अप्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, वे इस देश के लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ से वे शिक्षा लेकर आ रहे हैं, वहाँ से धन लेकर आ रहे हैं, वहाँ से सम्पत्ति लेकर आ रहे हैं, वहाँ से तकनीक लेकर आ रहे हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ हैं, जिनको यहीं जीना है, यहीं मरना है, उनके साथ केवल दुर्बलता लगी हुई है, उस दुर्बलता के कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते, उनके मताधिकार को रोक दिया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि बड़े-बड़े निर्वाचनों में भी 50 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं होता, 60 प्रतिशत से अधिक मतदान नहीं होता और 50 या 60 प्रतिशत मतदान होने के पश्चात् जो 40 या 50 प्रतिशत मतदाता वंचित रह जाते हैं, वे वंचित मतदाता उनका नाम होते हुए भी मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके बारे में हमने क्या किया है? क्या हम अनिवार्य मतदान की व्यवस्था नहीं कर सकते या दबंगों से उनकी रक्षा का कोई प्रावधान नहीं कर सकते? आज भी कई लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी ताकत के बल पर एक बार नहीं, बल्कि दो-दो, तीन-तीन बार वोट डाल कर आते हैं, जिस मताधिकार का प्रयोग उनका नहीं है, वे करते हैं, दुरुप्रयोग करते हैं। उनको रोकने के बारे में हमने क्या उपाय किए हैं? कोई उपाय नहीं! 60 वर्ष के बाद भी हम समुचित पद्धति का विकास नहीं कर पाए हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी अनेक खामियाँ हैं, जिन खामियों को ठीक करने का प्रयत्न इस संशोधन विधेयक में होना चाहिए था। क्या हम बार-बार संशोधन विधेयक लाते रहेंगे? क्या हम 60 वर्षों के बाद भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को परिपूर्णता नहीं दे पाएँगे? यदि इस प्रकार की खामियाँ हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप चार महीने और रुक जाते। जब आप चार वर्ष में केवल सत्यापन वाला शब्द खोज कर ला पाये हैं, तो दो-चार महीने और रुक कर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करते और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदाता सूची कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, इस पर सभी दलों के सुझाव लेने के बाद, यदि आप सर्वसम्मत, परिपूर्ण विधेयक लाते, तो शायद देश के हित में होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

महोदय, भारत के अन्य भाग के लोग कश्मीर जाकर सम्पत्ति नहीं रखीद सकते। तर्क दिया जाता है कि वहाँ की संस्कृति में परिवर्तन हो जाएगा, हम वहाँ की मूल संस्कृति को प्रभावित कर देंगे, इसलिए वहाँ जाकर भारत का कोई व्यक्ति सम्पत्ति में भागीदार नहीं बन सकता। लेकिन कश्मीर का व्यक्ति यहाँ आ सकता है। अभी-अभी हम लोग गोवा गए थे। गोवा में कश्मीर के अनेक लोगों ने अपने पर्यटन के स्थान बना लिए, सम्पत्ति खरीद ली। क्या वहाँ की मूल संस्कृति प्रभावित नहीं हो रही है? क्या बड़ी संख्या में वहाँ जाकर वे लोग वर्चस्व स्थापित नहीं कर लेंगे, गोवा की मूल संस्कृति प्रभावित नहीं होगी? ऐसी बातों के ऊपर पर्याप्त विचार होना चाहिए था। मतदाता सूची या लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक बनाते समय भी कहीं न कहीं इन सब बातों के ऊपर आप विचार करते और उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रत्यन करते...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): समाप्त हो गया न। धन्यवाद, शर्मा जी।

श्री रघुनन्दन शर्मा: सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो निर्वाचक मताधिकार से वंचित हैं, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, किन्तु यह कानून बार-बार संशोधित करना पड़े, इसके बजाए लोकतंत्र में विश्वास करने वाले राजनैतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार-विमर्श होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप दोबारा बैठ कर उसके बारे में विचार कर सकें और इस लोक प्रतिनिधित्व विधेयक में फिर से ऐसा कोई संशोधन ला सकें कि देश के समस्त नागरिक चाहे वे कमजोर हों या सबल, सभी मतदाता बन सकें, निर्वाचक बन सकें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सोचता हूं कि यदि इन खामियों को दूर करते हुए हम विचार करेंगे तो इसमें परिपूर्णता आ जाएगी, व्यापकता आ जाएगी और सबके साथ हम न्याय कर सकेंगे। प्रवासी भारतीयों के बारे में आप यह बिल लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): सर, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री जी जो बिल लाए हैं...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I believe, you are aware that we also have to take next Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I will be very brief in making my observations.

सर, यह एक बहुत ऐतिहासिक बिल है। मेरे ख़याल से बहुत दिन से यह मांग चली आ रही थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि डिबेट में बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। इसमें लोग नॉन-रैज़िडेंट इंडियंस, पीआईओ, ओसीआई, सबको मिलाकर समझ रहे हैं कि उनको कोई मताधिकार मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं और बाहर रह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में लाने की बात कही गई है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा कदम है और बहुत दिन से इसकी मांग हो रही थी। सरकार के माध्यम से इस तरह का जो कदम उठाया जा रहा है, वह इस मंशा को जाहिर करता है कि ऐसे लोग, जो भारत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, विदेशों में रह करके भी जिनका दिल भारत में है और जो यहां के लोकतंत्र के साथ अपना जुड़ाव देखना चाहते हैं, उनको एक माध्यम मिल सके। उनके लिए यह एक बहुत अच्छी चीज़ है।

कुछ चर्चा बिहारी मज़दूरों के बारे में हुई थी कि दूसरी जगह उनको वोट का अधिकार नहीं है या जो बाहर नौकरी करने गए, उनको वहां पर अधिकार नहीं है, इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि वे तो देश के अंदर ही हैं इसलिए वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार तो उनको है ही। वहां पर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, इसलिए इसके माध्यम से उनको मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। मैं तो मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि इंडियन एम्बैसीज़ में ही वोटिंग की व्यवस्था कराई जाए, ताकि उनको वोट देने के लिए यहां पर न आना पड़े। अगर हो सके तो जिनको डूअल सिटिज़नशिप दी गई है, पीआईओ इत्यादि, उनका नाम भी आप इसमें कंसिडर कर सकें, तो अच्छा रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): धन्यवाद। Now Shri Ram Kripal Yadav. यादव जी, आपने डिस्कशन शुरू होने के बाद अपना नाम दिया, फिर भी मैं आपका नाम बुला रहा हूं और आपको बोलने का चांस दे रहा हूं, इसलिए आपको पांच मिनट के अंदर खत्म करना है।

SOME HON. MEMBERS: Excellent Hindi, Sir.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): सर, आपने मुझे बोलने का विशेष अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं।

सर, मैं "लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010" के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। देश के बाहर लाखों लोग अपनी रोज़ी-रोटी, रोज़गार, शिक्षा और अन्य दूसरे कामों के लिए रह रहे हैं और बहुत व्यापक पैमाने पर रह रहे हैं। वे अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन ला कर देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का काम भी कर रहे हैं। उनको आपने मतदान का अधिकार देने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर इसका मैं जितना भी स्वागत करूं, कम है।

सर, देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा और राष्ट्र के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

महोदय, इसके साथ ही राष्ट्र की भावनाओं के प्रति उनका जुड़ाव भी रह पाएगा, इसलिए यह कदम बहुत ही स्वागतयोग्य है।

सर, देश के विभिन्न भागों से लाखों-लाख की संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं। मैं बिहार प्रदेश से आता हूँ। वहाँ के लोग काफी तादाद में बाहर जाकर अपना रोज़ी-रोजगार कर रहे हैं। चूँकि बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है, जहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है और फटेहाली है, इसकी वजह से वहाँ के लोग अपने प्रदेश से बाहर देश के अदंर के विभिन्न इलाकों में रहते हैं और अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, वहीं बिहार से विदेशों में भी जाकर, खास तौर पर खाड़ी का जो इलाका है, वहाँ पर निवास करके वहाँ से अपनी कमाई लाकर, वहाँ की पूँजी यहाँ लाकर ये लोग अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। यह और बात है कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए अपने देश में कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में रहने वाले, खासकर जो रोज़ी-रोजगार करने वाले लोग हैं, जो मेहनतकाश लोग हैं और जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने देश में ही रोजगार मिल जाए। वे लोग तो मजबूरी में ही विदेश जाते हैं। उनके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आजादी के 63-64 वर्षों बाद भी आज अगर किसी को मिट्टी काटने या अन्य छोटे-छोटे काम करने के लिए अपने परिवार को, अपने बाल-बच्चों को छोड़ कर विदेश जाना पड़ता है, तो वह वहाँ कितनी परेशानी में रहता होगा, इसके बारे में सोचने पर बड़ा ही हृदयविदारक सीन नजर आता है। दूसरे देशों में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर आप मतदान का अधिकार तो दे रहे हैं, मगर अपने देश में बिहार-जैसे गरीब प्रदेशों में निवास करने वाले जो गरीब मजदूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और उनको रोजगार के अवसर देने के बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है, ताकि उनको मजबूरी में विदेश न जाना पड़े। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

सर, मुझे एक बात समझ में नही आई। उनको मतदान के जो अधिकार मिलेंगे, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। विदेश में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने देश में आना होगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक छोटे-से आम आदमी या गरीब मजदूर के बहुत-सारे रुपए खर्च होंगे। मैं समझता हूँ कि आप उनको यह अधिकार दे तो रहे हैं, लेकिन यदि उनके लिए इसकी व्यवस्था वहाँ के दूतावासों में नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके साथ यह अन्याय होगा और आपकी यह मंशा साफ नहीं होगी। आप उनको मतदान करने की व्यवस्था वहीं करें। विदेशों में जो अपने दूतावास हैं, आप वहीं उनको

मतदान करने की व्यवस्था करें। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है। अगर वहीं पर उनके लिए इसकी व्यवस्था कर दें, तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण होगा। ...**(समय की घंटी)**... सर, मेरा एक मिनट बचा है। आपने मुझे पाँच मिनट बोलने कहा था।

उपसभाध्यक्ष **(प्रो. पी.जे. कुरियन)**: ठीक है, एक मिनट और बोल लीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और उन पर यह एक बड़ा उपकार होगा। निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी की जो भावना है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनको मतदान में हक देना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो यह अव्यवहारिक होगा। इसके लिए वह वहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं। आगामी 2-3 महीने के दरम्यान हमारे बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ के लोग हजारों-लाखों की तादाद में बाहर हैं। अगर उनको इसका मौका मिल जाता है, पता नहीं आने वाले दो-तीन महीने के अंदर इस कानून का क्या स्वरूप होगा, तो वे मतदान कर पाएँगे या नहीं, यह अलग बात है। अगर माननीय मंत्री जी उनके लिए यह व्यवस्था वहीं पर कर दें, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। वे लोग बहुत गरीब हैं और इसके लिए यहाँ नहीं आ सकते। जो process है, जो प्रक्रिया है, उसमें वे लोग वहाँ पर छः महीने या साल भर अथवा दो साल या तीन साल के contract पर जाते हैं। उस contract को तोड़ कर वे वापस कैसे आ सकते हैं? इसलिए, इस पर भी इनको सोचना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष **(प्रो. पी.जे. कुरियन)**: आपका समय पूरा हो गया। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं एक लाइन कह कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष **(प्रो. पी.जे. कुरियन)**: ठीक है, आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपने बहुत अच्छा बोला।

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं मतदाता सूची के बारे में कह रहा था। उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने जो कहा, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। चूँकि वे यहाँ पर सशरीर उपस्थित नहीं हैं, तो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आएगा। उनका नाम मतदाता सूची में कैसे आएगा और किस तरह से वे मतदान में भाग ले सकेंगे, जब माननीय मंत्री जी जवाब दें तो इस बात को जरूर स्पष्ट करें।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात इस विश्वास के साथ समाप्त करता हूँ कि इसमें जो खामियाँ हैं, उनको दूर करेंगे, माननीय सदस्यों ने जो अपनी भावनाएँ मंत्री जी के समक्ष रखी हैं, ...**(समय की घंटी)**... उन पर जरूर विचार करेंगे और विदेशों में रह रहे उन गरीब लोगों को सही मायने में मतदान करने का अधिकार मिले, इसका प्रावधान जरूर करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The Minister of Overseas Indian Affairs wants to intervene.

THE MINISTER OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (SHRI VAYALAR RAVI): Sir, I stand before the House to express the gratitude to millions of Overseas Indian workers and Overseas Indians living abroad. I accept their long-standing demand to enroll their names in the voters' list enabling them to vote, whenever it takes place.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Mr. Vice-Chairman, Sir, the right to vote is one of the most sacrosanct civil rights. In fact, it has been said by all the hon. Members that the services which have been rendered by these NRIs are really outstanding. As our distinguished Member, Shri Javadekar, has said, the contribution that they render to the foreign exchange reserves of this country is phenomenal, particularly from Kerala, Tamil Nadu, Goa and many other States. But we don't allow them to directly participate in the democracy. This right has been denied to them and that is why everyone agrees that we should provide them

the right to vote. After all, they are the citizens of the country. In fact, the right to vote, as demanded by the citizens of India living abroad, is their legitimate right. We are not doing any charity to them. We are acknowledging today that they have a right to vote and they have a right to be citizens of India, and we are here to recognize that right. It is not the right which is conferred on them; it is the right which is inherent to them. This is the basic truth which we need to understand. In fact, the Bill came in 2006 before the Parliament. The Standing Committee gave its 16th Report on it. The Standing Committee gave certain suggestions. We have incorporated those suggestions and right to vote is to be given to them.

In fact, many wide-ranging suggestions have been given here on various amendments to the comprehensive electoral reforms. I can tell the House that we have already constituted a Committee to sort out the issues and we would like to bring a comprehensive electoral reform. Maybe in October or November we are going to have a National Consultation on Comprehensive Electoral Reforms. Many of the suggestions which have been reflected by the hon. Members today can definitely be incorporated, and I would rather invite many of you to the National Consultation which will be held for two days. Ultimately, we will come to a precise decision what needs to be done for our electoral reforms. This is one thing which I would like to say. At the same time, I do agree with Shri Javadekar*ji* when he said *...(Interruptions)...* Even those persons who have been included in the voters' list are deprived of their right to vote. When they go to cast their vote, they find that their names are not there. These are all the deficiencies. We need to address them. I do agree that there are certain rigidities when it comes to casting of votes by *Jawans* who are posted to border areas or far off areas. Even though provisions have been made, they are not being implemented. We need to make rules. The Government will definitely consult the Election Commission of India. Many of these issues can be tackled not by amendment to the Act or bringing in new provisions, but by making appropriate rules.

I do agree with our senior Member, Shri Shantaram Laxman Naik when he says that a number of letters are written by the Election Commission of India, and, those are being converted into rules or laws. Yes, we need to rationalize; we need to codify many things. Ultimately, in case of any authority, discretion many a time may amplify everything, and, that may create rigidity. We need to address that. In the process of national consultation, we will definitely address all those things. If there are many pages of rules, many pages of instructions, ultimately, they will create more confusion instead of really clarifying the things. We would definitely address this issue. At this time, after we have undergone this kind of a great democratic ritual, namely, the elections, we need to address those problems. I can assure the House that we will definitely address those problems.

As far as NRIs are concerned, I would like to say that it is very clearly defined in the first page of the Bill itself that every citizen of India, (a) whose name is not included in the electoral

roll, and, (b) who has not acquired citizenship of any other country, shall be entitled to have his name registered. There is no question of addressing the dual citizenship. If he has acquired the citizenship of any other country, he will not be entitled. The Bill is very clear about this. It is a very simple piece of legislation of one and a half page, which is confined only to NRIs only. We will definitely address other issues, which have been raised by you, but not now.

As far as 'voting right' and the 'right to contest' are concerned, you have to distinguish them. The present proposal is only to confer voting rights on the citizens of India who are not citizens of any other country, to get themselves enrolled and cast their votes in their relevant constituency as per the place shown in their passports. The Bill does not deal with the right to contest at all, for which other relevant laws would apply. So, we are not addressing that issue. It is not one and the same. It is distinguished very clearly. We will address other issues later but not here.

Another question, which I would like to address, is with regard to the migrant workers. It is an important issue. They also find their names missing. It is not only related to persons or citizens residing outside India, it is also related to the migrant labourers, farm labourers or the construction workers. Yes, we can provide rules for them. We will properly verify before deletion. The other day, we have brought in an amendment, which provides for that. The Deputy Commissioner or the District Magistrate have been conferred the right to inquire into the deletion, exclusion or the addition of names. So, we have already passed a law and the law is already in force.

As far as ordinary resident is concerned, to supplement the other things, which I have said, we already have the General Principles of Voter Registration. It has been very clearly mentioned there under the meaning of "ordinarily resident". It says, "A person is said to be ordinarily resident in a place if he uses that place for sleeping. He need not be eating in that place and may be eating from a place outside". Lot of details have been given. It also says, "Temporary periods of absence from this ordinary place of stay can be ignored. It is not necessary that the period of stay should be continuous for any particular length of time and should be without any break." Further, it says, "it is purely a question of fact whether a person is ordinarily resident at a particular place or not. Mere absence for some time will not deprive a person of the qualification of ordinary residence". So, it is very clear.

I know very well the situation on the ground. When the enumerator goes to a place, he may not find that person. That person may be absent at that time, but he may be coming back in the evening. I have found that in these situations, it is ordinary practice that their names are not included. This happens but we need to address these problems. We will definitely address it.

I think, I have addressed many of the points that were raised. It is a simple Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Yes, you have covered most of the points. I think, you have covered all the points. Thank you very much. Okay. The question is:

That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up the Prevention of Torture Bill, 2010. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, we want to know about the clarifications on the statement which had been made by the Home Minister. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up the Prevention of Torture Bill. After that, it will be taken up. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, first we want the clarifications to be taken up. ...*(Interruptions)*... Sir, the Home Minister is here. Please take up the clarifications first. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We will take it up. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, you take up the clarifications first. ...*(Interruptions)*... Sir, please... ...*(Interruptions)*... This we cannot accept, Sir. ...*(Interruptions)*... Please take up the clarifications today, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Brindaiji, you please read the List of Business. It is given there that the clarifications will be taken up before the House rises for the day. ...*(Interruptions)*... Now, therefore, I have to take up the Prevention of Torture Bill. After that, we will take up the clarifications. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: No, Sir. ...*(Interruptions)*... No, Sir. ...*(Interruptions)*... Clarifications should be taken up first. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Take up the Salary Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: First the clarifications... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We can take it up. ...*(Interruptions)*... We will take it up. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, take the clarifications first. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I tell you, we will do that. ...*(Interruptions)*... We will do that. ...*(Interruptions)*... Listen... ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, take the sense of the House. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I tell you... ...*(Interruptions)*... Let him move the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Let him only move. ...*(Interruptions)*... We will not take up further discussion today. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is what I am saying. Let him introduce. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, first take up the clarifications. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): I am giving the clarifications today. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let him move it. ...*(Interruptions)*... We will decide it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Give the clarifications before the Torture starts. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Brindaji, we have to decide.. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, take up the clarifications before... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please... ...*(Interruptions)*...

The Prevention of Torture Bill, 2010

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

That the Bill to provide punishment for torture inflicted by public servants or any person inflicting torture with the consent or acquiescence of any public servant, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was proposed.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I have moved the motion here... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no... ...*(Interruptions)*... What do you want to say? ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Sir, we will not discuss it today. We need some time to discuss this in our Party meeting. He has moved it, but we will take it up tomorrow. ...*(Interruptions)*...